गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 270
दि. 01.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बलूचिस्तान फिर दहला, समन्वित हमलों से फैली दहशत, सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच भीषण संघर्ष

(जीएनएस)। पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक साथ कई जिलों में बड़े और समन्वित हमले कर सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया। इन हमलों ने न सिर्फ आम लोगों में डर का माहौल पैदा किया, बल्कि पूरे प्रांत को हाई अलर्ट पर ला दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 37 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है। दिनभर चली गोलीबारी और तलाशी अभियानों के कारण कई इलाकों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। शनिवार सुबह हालात तब बिगड़े, जब लगभग एक ही समय पर क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में गोलीबारी और आत्मघाती हमलों की कोशिशें सामने आईं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हमलावरों ने पुलिस चौकियों, गश्ती दलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। क्वेटा में स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रही, जहां कई घंटों तक गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। इसी दौरान चार पुलिसकर्मियों के शहीद होने की पुष्टि की गई, जबकि अन्य इलाकों से भी हताहतों की खबरें सामने आती रहीं। हमलों के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक जवाबी कार्रवाई शुरू की। शहरों के प्रवेश और निकास मार्ग सील कर दिए गए, संदिग्ध इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और हवाई निगरानी भी बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी

अधिकारियों का कहना है कि त्वरित और समन्वित कार्रवाई के कारण उग्रवादियों की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, अन्यथा नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ों के दौरान 37 उग्रवादियों को ढेर किया गया, जिनमें BLA के कई प्रशिक्षित लड़ाके शामिल बताए जा रहे हैं।

इन हमलों की जिम्मेदारी खुद बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि यह उसके तथाकथित 'ऑपरेशन हेरोफ' का हिस्सा है और इसका दूसरा चरण शुरू किया जा चुका है। BLA का दावा है कि उसका मकसद सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढांचे को निशाना बनाना है, ताकि वह अपने राजनीतिक और क्षेत्रीय एजेंडे को आगे बढ़ा सके। संगठन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे हमले और तेज किए जा सकते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है।

हमलों के बाद पूरे बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई है। क्वेटा समेत कई शहरों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि फिलहाल किसी नागरिक के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि स्थानीय स्तर पर लोगों में भय और अनिश्चितता का माहौल साफ देखा जा सकता है। कई बाजार समय से पहले बंद हो गए और लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर रहे।

बलूचिस्तान में हिंसा और विद्रोह का यह सिलसिला दशकों पुराना है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से भरपूर है। इसके बावजूद स्थानीय बलूच समुदाय लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और संसाधनों के असमान बंटवारे का आरोप लगाता रहा है। इन्हीं असंतोषों के बीच अलगाववादी संगठनों ने हथियार उठाए और समय-समय पर बड़े हमलों को अंजाम दिया।

हाल के वर्षों में BLA और अन्य उग्रवादी संगठनों की रणनीति और अधिक आक्रामक होती दिखी है। पहले जहां हमले मुख्य रूप से सुरक्षा बलों तक सीमित रहते थे, वहीं अब अन्य प्रांतों के नागरिकों, विकास परियोजनाओं और विदेशी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ी परियोजनाएं भी कई बार हमलों के केंद्र में रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

मार्च 2025 की घटना अभी भी लोगों की स्मृति में ताजा है, जब BLA ने सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और देशभर में आक्रोश फैल गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हमले उसी रणनीति का विस्तार हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को अस्थिर करना और भय का माहौल बनाना है।

पाकिस्तानी सरकार और सेना बार-बार यह दावा करती रही है कि उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राजनीतिक संवाद, विकास और सुरक्षा—इन तीनों मोर्चों पर संतुलन बनाए बिना स्थायी शांति संभव नहीं मानी जा रही। फिलहाल, शनिवार के इन हमलों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में शांति अभी दूर की मंजिल है और वहां हालात किसी भी वक्त फिर विस्फोटक हो सकते हैं।

निवेश के सपने और भरोसे का टूटना: 3000 करोड़ के कथित घोटाले में नामचीन सितारों पर कानूनी शिकंजा

(जीएनएस)। देश के बड़े निवेश घोटालों में गिने जा रहे एक मामले ने झारखंड से लेकर दिल्ली और मुंबई तक हलचल मचा दी है। इस कथित 3000 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडे समेत कई फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। निवेश योजना के प्रचार और निवेशकों को आकर्षित करने के आरोपों को लेकर जमशेदपुर की अदालत ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे फिल्मी दुनिया और राजनीति—दोनों ही क्षेत्रों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह मामला गाजियाबाद स्थित कंपनी Maxizone Touch Private Limited से जुड़ा हुआ है, जिसने कथित तौर पर निवेशकों को हर महीने करीब 15 प्रतिशत ब्याज देने का आकर्षक वादा किया था। आरोप है कि इसी भारी मुनाफे के लालच में देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोगों ने कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने इस योजना के प्रचार में नामचीन फिल्मी सितारों को देखा, तो उनका भरोसा और मजबूत हो गया। कई निवेशकों का दावा है कि उन्होंने केवल सेलेब्रिटीज की मौजूदगी और प्रचार के कारण इस कंपनी को विश्वसनीय मान लिया।

शुक्रवार को इस मामले में जमशेदपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता सुबोध कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (षड्यंत्र) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब साकची थाना में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पुलिस को जांच का रास्ता साफ हो गया है। शिकायतकर्ता के वकील विद्या सिंह के अनुसार, निवेशकों को जानबूझकर गुमराह किया गया और एक संगठित तरीके से उन्हें ऊंचे मुनाफे का सपना दिखाया गया। उनका कहना है कि यदि प्रचार में शामिल हस्तियां सामने नहीं आतीं, तो शायद आम लोग इस योजना में निवेश करने से पहले कई बार सोचते। यही वजह है कि सेलेब्रिटी प्रचार को इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी माना जा रहा है।

निवेशकों के नुकसान की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शिकायत के अनुसार, अकेले जमशेदपुर के निवेशकों के लगभग 150 करोड़ रुपये इस कंपनी में फंसे हुए हैं, जबकि पूरे झारखंड में यह आंकड़ा करीब 600 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कथित घोटाले की कुल राशि लगभग 3000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। कई ऐसे निवेशक भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी जीवनभर की बचत या जमीन-जायदाद बेचकर 20 से 30 लाख रुपये तक इस योजना में लगा दिए थे।

समस्या तब गहराई, जब तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद निवेशकों को न तो वादा किया गया ब्याज मिला और न ही उनका मूलधन वापस किया गया। शुरुआत में कंपनी की ओर से भुगतान में देरी की बात कही गई, लेकिन बाद में निवेश पूरी तरह अटक गया। निवेशकों का आरोप है कि लगातार टालमटोल के बाद कंपनी ने खुद को आर्थिक संकट में बताते हुए भुगतान करने से असमर्थता जता दी। वहीं, कंपनी की ओर से यह दावा किया गया है कि उसे भारी व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते निवेशकों को समय पर पैसा लौटाना संभव नहीं हो सका।

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर इस सवाल को केंद्र में ला दिया है कि निवेश योजनाओं के प्रचार में फिल्मी सितारों और सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। आम निवेशकों का कहना है कि जब कोई लोकप्रिय चेहरा किसी योजना का प्रचार करता है, तो लोग उसे सुरक्षित और भरोसेमंद मान लेते हैं। ऐसे में यदि योजना फर्जी या अव्यवहारिक निकलती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है।

किश्तवार में सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे से बढ़ी सतर्कता, Operation TRASHI-I के तहत घेराबंदी तेज

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता उस समय और बढ़ गई, जब थकरेई इलाके में स्थानीय लोगों को पाकिस्तान से जुड़ा एक संदिग्ध गुब्बारा और बैनर मिला। इस गुब्बारे और बैनर पर अंग्रेजी में "The Pakistan Foundation College for Girls, Narowal" और "Annual Sports Day 2026" लिखा हुआ था। जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस पर पड़ी, उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गुब्बारे और बैनर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर इसे सीमापार से हवा के जरिए भेजा गया संदिग्ध प्रचार सामग्री माना जा रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इसकी पड़ताल कर रही हैं। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है, जब किश्तवार जिले में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से 'Operation TRASHI-I' चला रहे हैं। यह अभियान घाटी में सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने, उनके ठिकानों का पता लगाने और इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सुरक्षा सूत्रों

के मुताबिक, डोलगाम और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में आतंकियों की आवाजाही और संपर्क को खत्म करने के लिए व्यापक तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों, पहाड़ी इलाकों और संभावित ठिकानों पर लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को समय रहते नाकाम किया जा सके।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सीमापार से इस तरह के गुब्बारे या बैनर भेजने की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध या माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे मामलों में छोटी-सी चूक भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सुरक्षा बल किसी भी संदिग्ध वस्तु को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। किश्तवार में हालात संवेदनशील बने हुए हैं और हर सूचना की गहन जांच की जा रही है।

इसी बीच व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवार का दौरा कर जमीनी हालात और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन में तैनात अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और उनके साहस तथा समर्पण की सराहना की। सेना कमांडर ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और क्षेत्र को पूरी तरह आतंक-मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

Operation TRASHI-I के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। इस अभियान में हवलदार गजेंद्र सिंह ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। 18 जनवरी को शुरू हुए इस आतंकवाद-रोधी अभियान के अगले ही दिन किश्तवार जिले के चतरू के सिंगपुरा क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। 19 जनवरी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। उनकी शहादत ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि घाटी में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाबल किस हद तक बलिदान देने को तैयार हैं।

व्हाइट नाइट कोर ने भी सोशल मीडिया के जरिए हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पोस्ट में कहा गया कि उन्होंने Operation TRASHI-I के दौरान बहादुरी से कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका अदम्य साहस, वीरता तथा कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। इस संदेश के बाद इलाके में तैनात जवानों का मनोबल और मजबूत हुआ है।

पाकिस्तानी गुब्बारे और बैनर की बरामदगी के बाद किश्तवार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सेना ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत सुरक्षाबलों को दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे हालात की गंभीरता को समझते हैं और सुरक्षाबलों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार लोगों से संवाद बनाए हुए है, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल Operation TRASHI-I के तहत तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आतंकवादी किसी भी तरह से माहौल खराब न कर सकें। किश्तवार में हालिया घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि घाटी में शांति बनाए रखने की लड़ाई अभी जारी है और इसमें सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी का शिकंजा पूर्व स्वास्थ्य निदेशक की करोड़ों की संपत्ति जब्त

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनकी और उनकी पत्नी की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के बीच ईडी ने भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित कुल 9.79 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मामला एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा है, जो लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील महकमे में अहम पद पर रहा।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा मामला लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ। लोकायुक्त ने अपनी जांच में पाया था कि डॉ. अमरनाथ मित्तल ने अपनी ज्ञात और वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में जब इस मामले में अवैध धन और संदिग्ध लेनदेन की परतें सामने आईं, तो प्रवर्तन निदेशालय ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के दायरे में लिया।

ईडी की विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आया कि डॉ. मित्तल की वैध आय करीब 60 लाख रुपये के आसपास थी, जबकि उनके द्वारा खरीदी गई

संपत्तियों और किए गए खर्च का कुल आंकड़ा लगभग 2.98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह करीब 2.38 करोड़ रुपये की संपत्ति को उनकी ज्ञात आय से अधिक और अवैध माना गया। अधिकारियों का कहना है कि यह अंतर सामान्य प्रशासनिक वेतन और भत्तों से कहीं ज्यादा है, जिसे किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता।

जांच एजेंसी का दावा है कि डॉ. मित्तल ने केवल अपने नाम पर ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी अलका मित्तल और 'ए.एन. मित्तल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)' के नाम पर भी कई चल और अचल संपत्तियां खरीदीं। ईडी के अनुसार, इसका मकसद अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाना और संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को अस्पष्ट करना था। इस तरह की व्यवस्था को जांच एजेंसियां आमतौर पर काले धन को सफेद दिखाने और कानून की नजर से बचने की रणनीति मानती हैं।

ईडी की पड़ताल में यह भी सामने आया कि अवैध धन को वैध रूप देने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन किए गए। इसमें लेयर्ड ट्रांजैक्शन, बेहिसाब नकदी और अज्ञात स्रोतों से जमा रकम का इस्तेमाल शामिल था। अधिकारियों के मुताबिक, संपत्तियों की खरीद-बिक्री और निवेश का पूरा पैटर्न इस बात की ओर इशारा करता है कि धन के स्रोत को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि इस मामले को केवल आय से अधिक संपत्ति तक सीमित न रखकर मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया गया।

इस केस का एक अहम पहलू यह भी है कि वर्ष 2012 में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी डॉ. अमरनाथ मित्तल ने कथित तौर पर नई संपत्तियों में निवेश जारी रखा। ईडी का कहना है कि एफआईआर के बाद पुरानी संपत्तियों को बेचकर जो धन प्राप्त हुआ, उसे नई संपत्तियों में लगाया गया, जिसे 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' की श्रेणी में रखा गया है। इसी कारण से समय के साथ कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 9.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

ईडी द्वारा जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड, भोपाल और रायसेन में स्थित आवासीय मकान और भूखंड, साथ ही कृषि भूमि भी शामिल है। जांच एजेंसी का कहना है कि ये सभी संपत्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवैध कमाई से जुड़ी हुई पाई गई हैं। फिलहाल इन संपत्तियों के लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और इन्हें न तो बेचा जा सकता है, न ही किसी अन्य के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अंतिम नहीं है और मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। यदि जांच के दौरान और संपत्तियों या खातों का पता चलता है, तो उन्हें भी कुर्क किया जा सकता है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन अधिकारियों के लिए जो सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। ईडी की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि भले ही मामला पुराना हो, लेकिन जांच एजेंसियां ऐसे मामलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय

डिजिटल नशा

बच्चों व किशोरों की सोशल मीडिया पर बढ़ती अति-सक्रियता अभिभावकों ही नहीं, देश के लिये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों का पढ़ाई से भटकाव व एकाग्रता में गिरावट समय की बड़ी फिक्र है। इसी बीच इकोनॉमिक सर्वे में सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से पहुंच का सुझाव एक स्वागत योग्य कदम है। सालों से, डिजिटल विस्तार को एक बिना शर्त अच्छे बदलाव के रूप में देखा जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि सोशल मीडिया तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डिजिटल लिटरेसी की खामियों को दूर करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने में डिजिटल क्रांति सहायक है। निश्चित रूप से आर्थिक सर्वे में इस बाबत उल्लेख एक असहज करने वाली सच्चाई को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह स्वीकार किया जा रहा है कि बिना रोक-टोक के डिजिटल एक्सपोजर तेजी से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है। सही मायनों में डिजिटल लत को मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली समस्या के रूप मे पहचानते हुए, सर्वे इस बहस को तथ्यों पर आधारित नीति बनाने की जरूरत बताता है। इसकी सिफारिश है कि उम्र के हिसाब से एक्सेस की सीमाएं तय करने, उम्र की वेरिफिकेशन के लिये प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही निर्धारित करने, बच्चों के लिये सरल डिवाइस बनाने और ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। सही मायनों में इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति का ही अनुसरण किया जा रहा है। वास्तव में बच्चों को सम्मोहित करने वाले डिजिटल डिजाइनों से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। जो कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों पर खासा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। निश्चित रूप से डिजिटल लत के शिकार होते बच्चों व किशोरों के, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण समय की मांग है। इसके अलावा इस बाबत सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देना भी उतना ही जरूरी है। तभी इस संकट का आशाजनक समाधान तलाशना संभव हो सकेगा।

वहीं दूसरी ओर, इस संकट से उबरने के लिये प्लेटफॉर्म लेवल सेफ्टी और फैमिली डेटा प्लान की भी मांग की जा रही है। जो पढ़ाई की जरूरत और मनोरंजन के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल का फर्क कर सके। इसके साथ ही हालिया आर्थिक सर्वे में इस बात को स्वीकार किया गया है कि माता-पिता पहले से ही यह जानते हैं कि व्यक्तिगत कंट्रोल बड़े पैमाने से इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि आस्ट्रेलिया व फ्रांस जैसे विकसित देशों में सरकारों को इस दिशा में सख्त पहल करनी पड़ी। एक ओर जहां आस्ट्रेलिया ने सोलह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगायी है, वहीं फ्रांस ने पंद्रह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक सीधी पहुंच को रोकने को कदम उठाये हैं। कुछ अन्य देशों में भी सरकारें तेजी से सख्त सीमाएं तय करने की दिशा में काम कर रही हैं। आज जहां भारत में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। वैसे भारत जैसे देश जहां युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां डिजिटल क्रांति से पूरी तरह अलग भी नहीं रहा जा सकता। ऐसे में एक नियम से ही सबको नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद हमें स्वीकारना होगा कि विदेशी प्लेटफॉर्मों से प्रसारित अपसंस्कृति भारतीय किशोरों को पथभ्रष्ट करने में घातक भूमिका निभा रही है। जिससे देश में किशोरों की यौन अपराधों में संलिप्तता का खतरा बढ़ रहा है। ये अपसंस्कृति न केवल समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रही है, बल्कि उनमें मानवीय संवेदनाओं का भी क्षरण कर रही है। जो किसी भी सभ्य समाज के लिये एक गंभीर चुनौती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक मूल्यों व संबंधों में शुचिता को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। इस बाबत सरकार की सख्त पहल और अभिभावकों की सजगता मिलकर ही समस्या का समाधान निकाल सकती है।

तेल के खेल में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता

भारत-वेनेजुएला वार्ता के बाद दुनिया में मची हलचल

> सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है।

भारत और वेनेजुएला के बीच कूटनीति ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस वार्ता का सीधा संबंध तेल से है और इसका परोक्ष असर भारत रूस निर्भरता घटाने, अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है।सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल आयात में प्रतिदिन कई लाख बैरल की कटौती कर सकता है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ऊर्जा सहयोग पर सहमति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक संदेश में कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा दृष्टि रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। दशकों तक कठोर सरकारी नियंत्रण के बाद अब कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। खोज, उत्पादन, वितरण

और विपणन में निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है। कर और रॉयल्टी घटाई गई हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुल्क और कम किए जा सकते हैं और विवादों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खोला गया है। इस तरह यह बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर की राष्ट्रीयकरण नीति को पलट दिया गया है।

अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाते हुए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी है। नया सामान्य लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के निर्यात, भंडारण, परिवहन और परिशोधन की अनुमति देता है, हालांकि भुगतान और कुछ देशों से जुड़े लेन-देन पर सख्त शर्तें रखी गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दिशा बदली है।

देखा जाये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ा है, व्यापार शुल्क भारी हुए हैं और प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति व्यवस्था जटिल हो गई है। इसी वजह से भारत अब तेल आयात के नए विकल्प तलाश रहा है। आयात के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रूस से तेल खरीद दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके साथ ही ओपेक देशों से आने वाले तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली है और आपूर्ति स्रोत बदलने शुरू कर दिए हैं।

इसी बीच, वेनेजुएला के नए कानून ने एक नई संभावना खोली है। उत्पादन और निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते जो तेल पहले मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह बेहतर कीमत और कम लागत के साथ खुले बाजार में उपलब्ध होगा। सरकारी आकलन के अनुसार, वेनेजुएला में इस साल उत्पादन में 18 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है, जबकि निजी अनुमान इससे भी तेज उछाल की ओर संकेत कर रहे हैं।

देखा जाये तो मोदी और रोड्रिगेज की बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामरिक संकेत है। भारत साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि वह किसी एक स्रोत या किसी एक धड़े के साथ नहीं रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक संप्रभुता की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुध्रुवीय नीति अनिवार्य है। वेनेजुएला के दरवाजे खुलना भारत के लिए अवसर की तरह है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार तक पहुंच सस्ती और स्थिर आपूर्ति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत को अमेरिकी शर्तों, भुगतान नियमों और भू-राजनीति की रस्साकशी में संतुलन भी साधना होगा।

सामरिक रूप से यह कदम रूस पर निर्भरता घटाकर भारत की सौदेबाजी की शक्ति को और बढ़ाता है। यदि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, साथ ही लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ के मंच पर भी यह संकेत जाएगा कि भारत ठोस साझेदारी करता है। वहीं वेनेजुएला ने नियम सरल कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक यथार्थ विचारधारात्मक जिद से बड़ा होता है। निजी निवेश, कम कर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और पारदर्शिता से ही उत्पादन बढ़ेगा और आम नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। भारत यदि यहां निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौते करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा।

बहरहाल, इस पूरी तस्वीर के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी विदेश नीति साफ दिखाई देती है। कच्चे तेल की खरीद और आपूर्ति के मोर्चे पर उन्होंने खुद को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल संकट से जूझ रही थी, तब भारत पर भी हर तरफ से दबाव था कि वह सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए बहुस्तरीय कूटनीति अपनाई। रूस से तेल खरीद जारी रखी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आपूर्ति संतुलित की और अब लैटिन अमेरिका की ओर रणनीतिक कदम बढ़ा दिये हैं। इसी संतुलित नीति का नतीजा रहा कि जहां यूरोप और अमेरिका में ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं। यह केवल आर्थिक प्रबंधन नहीं था, बल्कि वैश्विक दबावों के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था। देखा जाये तो मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली लगातार कुशल रणनीति के साथ फैसले कर रही है। यही आक्रामक यथार्थवाद आज के दौर की मांग है।

प्रेरणा

प्रकृति का मौन सत्य और मनुष्य की परीक्षा

धर्मयात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों का नहीं, बल्कि अनुभवों से उपजे गहन सत्यों का प्रवाह था। उनके प्रत्येक संवाद में जीवन की ऐसी व्याख्या छिपी होती थी, जो सामान्य घटनाओं को भी असाधारण अर्थ दे देती थी। एक बार की यह छोटी-सी घटना, जिसमें झरने का गंदला और फिर स्वच्छ होता जल शामिल है, वास्तव में मनुष्य, समय, धैर्य और प्रकृति के शाश्वत नियमों की गहरी समझ कराती है।

यात्रा करते-करते जब बुद्ध को थकान हुई, तो उन्होंने वृक्ष की छाया में विश्राम किया। यह दृश्य स्वयं में प्रतीकात्मक है—मनुष्य की थकान और प्रकृति की शीतल गोद। वहीं से उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द को जल लाने को कहा। आनन्द जब झरने पर पहुँचे, तो देखा कि कुछ समय पहले गुज़री बैलगाड़ी के कारण पानी मटमैला हो गया था। यह स्थिति हमारे जीवन की उन परिस्थितियों जैसी है, जब बाहरी घटनाएँ हमारे मन, विचार और भावनाओं को अशांत कर देती हैं। आनन्द ने स्वच्छ जल की खोज में अन्यत्र जाने का निर्णय लिया, जो स्वाभाविक भी था। पर बुद्ध ने उन्हें रोका और धैर्य रखने को कहा।

यहाँ बुद्ध का आग्रह केवल जल के लिए नहीं था, बल्कि जीवन को समझने का एक सूक्ष्म संकेत था। कुछ समय बाद जब आनन्द पुनः उसी झरने पर पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि गंदला पानी बह चुका था और झरना फिर से निर्मल हो गया था। यह दृश्य बताता है कि समय स्वयं अशुद्धियों को बहा ले जाता है, यदि हम हस्तक्षेप किए बिना उसे अपना कार्य करने दें। बुद्ध का यह कथन कि "परिस्थिति बदल जाती है, प्रकृति स्थिर रहती है" केवल दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहारिक सूत्र है।

मनुष्य अक्सर परिस्थितियों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह मूल स्वभाव, यानी अपनी प्रकृति, को भूल बैठता है। क्रोध, भय, निराशा, ईर्ष्या—ये सब परिस्थितियों से उपजी अस्थायी अवस्थाएँ हैं। पर मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके संस्कारों, मूल्यों और अंतर्निहित गुणों से होती है। जैसे झरने का स्वभाव निर्मल बहना है, वैसे ही मनुष्य की श्रेष्ठ प्रकृति करुणा, सत्य, धैर्य और विवेक है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विकट क्यों न हों, वे स्थायी नहीं होतीं।

आज के समय में यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। तेज़ प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव, आर्थिक अस्थिरता और व्यक्तिगत संघर्ष मनुष्य के मन को बार-बार गंदला कर देते हैं। ऐसे में कई लोग जल्दबाज़ी में निर्णय ले लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं या स्वयं से ही हार मान लेते हैं। यदि वे थोड़ा ठहरकर देखें, तो पाएँगे कि जैसे झरने का गंदलापन अस्थायी था, वैसे ही उनके जीवन की कठिनाइयाँ भी समय के साथ बह जाएँगी। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण गुण है संतुलन। वह किसी एक अवस्था में अटकी नहीं रहती। ऋतुएँ बदलती हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है। दुख के बाद सुख और असफलता के बाद सफलता का मार्ग भी इसी संतुलन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस प्राकृतिक नियम को समझ लेता है, वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके बह जाने की प्रतीक्षा करता है, स्वयं को सुदृढ़ बनाए रखता है।

बुद्ध का संदेश यह भी सिखाता है कि श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की, वैसे ही सच्चे गुण समय आने पर स्वयं चमक उठते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ईमानदारी, मेहनत और करुणा है, तो प्रारंभ में उसे अनदेखा किया जा सकता है, पर दीर्घकाल में वही गुण उसे विशिष्ट बनाते हैं। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती; वह देर कर सकती है, पर निष्पक्ष रहती है।

यह कथा हमें धैर्य का मूल्य भी सिखाती है। आज के युग में अधीरता एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं—तुरंत सफलता, तुरंत मान्यता, तुरंत समाधान। पर प्रकृति तात्कालिकता के नियम से नहीं चलती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुँचने में धैर्य चाहिए। इसी तरह, मनुष्य के जीवन में भी स्थायी उपलब्धियाँ समय और निरंतर प्रयास से ही मिलती हैं।

अंततः, बुद्ध का यह संदेश आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम परिस्थितियों के अनुसार बदल रहे हैं या अपनी प्रकृति को सँभालकर रख पा रहे हैं। यदि हम हर बाहरी घटना से विचलित हो जाते हैं, तो हम भी उस गंदले पानी जैसे हो जाते हैं जो थोड़ी-सी हलचल से अशुद्ध हो जाता है। पर यदि हम अपनी मूल शुद्धता बनाए रखते हैं, तो समय स्वयं हमारे पक्ष में बहने लगता है।

प्रकृति का मौन सत्य यही है कि वह अस्थायी अवरोधों से नहीं डरती। वह जानती है कि अंततः उसका स्वभाव ही विजयी होगा। मनुष्य यदि इस सत्य को आत्मसात कर ले, तो जीवन की यात्रा अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण हो सकती है। बुद्ध की यह छोटी-सी कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और आत्मगुणों की रक्षा सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि अंत में प्रकृति की प्रबलता ही सत्य को स्थापित करती है।

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन—जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जेसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी।

इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है।

उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे।

हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से 0.74C अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं।

भारत के मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर होने से पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में न के बराबर बर्फ गिरी। गढ़वाल में इस साल जनवरी में बर्फबारी का अभाव देखा गया। ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है। कम हिमपात के चलते जटामांसी और कुटकी जैसी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ीबूटियां विलुप्त हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो ड्रॉट या 'बर्फ का सूखा' जैसी स्थिति बन रही है। विशेष रूप से 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है।

अभियान

जब आपकी इच्छाशक्ति बन जाए जादू: टैरो का 'द मैजिशियन' और जीवन में

मनुष्य हमेशा से भविष्य के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। यही जिज्ञासा उसे कभी आकाश में तारों की चाल समझने को प्रेरित करती है, तो कभी अंकों, रेखाओं और प्रतीकों में छिपे संकेतों को पढ़ने की ओर ले जाती है। जन्मकुंडली, न्यूमेरोलॉजी और हस्तरेखा शास्त्र के साथ-साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी इसी जिज्ञासा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। टैरो केवल भविष्यवाणी की विधा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के वर्तमान, उसकी मानसिक स्थिति और आने वाली संभावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण भी करती है। टैरो काड्र्स में रंग, अंक, चित्र और पंचतत्व—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—मानव जीवन की ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन-सी शक्तियाँ सक्रिय हैं और आगे का मार्ग किस दिशा में जा सकता है।

टैरो कार्ड देखने में ताश के पत्तों जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ साधारण नहीं होता। हर कार्ड पर बनी आकृति, हर रंग और हर संकेत का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। टैरो डेक में कई कार्ड होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में बाँटा गया है। मेजर आर्काना के कार्ड जीवन के बड़े बदलावों, आत्मिक विकास और भाग्य से जुड़े माने जाते हैं। इन्हीं मेजर आर्काना काड्र्स में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली कार्ड है—'द मैजिशियन'। जब टैरो रीडिंग में यह कार्ड निकलता है, तो इसे सफलता, अवसर और सौभाग्य का स्पष्ट संकेत माना जाता है।

'द मैजिशियन' कार्ड को मेगस के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्ड सृजन की शक्ति, चेतन नियंत्रण और इच्छाशक्ति का प्रतीक है। टैरो दर्शन के अनुसार, यह कार्ड यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास वे सभी संसाधन मौजूद हैं, जिनकी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसे उन संसाधनों का सही उपयोग करना है। यह कार्ड बताता है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पक्ष में बनने लगी हैं और यदि वह सही दिशा में प्रयास करे, तो सफलता लगभग सुनिश्चित है।

इस कार्ड की छवि अपने आप में बहुत गहरी प्रतीकात्मकता लिए होती है। इसमें एक युवा जादूगर या साधक को दिखाया जाता है, जिसके एक हाथ से आकाश की ओर और दूसरे हाथ से धरती की ओर संकेत किया गया होता है। इसका अर्थ है—"जैसा ऊपर है, वैसा ही नीचे है।" यानी विचारों और कल्पनाओं को भौतिक रूप देने की शक्ति। उसके सामने एक मेज पर चार वस्तुएँ रखी होती हैं—छड़ी, तलवार, कप और पेंटाकल। ये चारों वस्तुएँ चार तत्वों और चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह संकेत देता है कि 'द मैजिशियन' सभी तत्वों और शक्तियों का संतुलित उपयोग करना जानता है। टैरो में 'द मैजिशियन' को कौशल, बुद्धिमत्ता, संवाद क्षमता, रचनात्मकता और रणनीतिक सोच से जोड़ा जाता है। यह कार्ड बताता है कि व्यक्ति केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि समझदार भी है। वह परिस्थितियों को भली-भांति समझकर अपने हित में निर्णय ले सकता है। इसमें चालाकी का तत्व भी शामिल है, लेकिन यह नकारात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धि का संकेत है। जीवन में हर लक्ष्य सीधी राह से नहीं मिलता; कभी-कभी कूटनीति, समझौता और रणनीति की भी आवश्यकता होती है। 'द मैजिशियन' इसी संतुलन का प्रतीक है। यह कार्ड बेचैनी और सक्रियता को भी दर्शाता है। 'द मैजिशियन' स्थिर रहना पसंद नहीं करता। वह हमेशा कुछ नया सीखने, नया करने और आगे बढ़ने की सोच में रहता है। यह बेचैनी दरअसल उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। टैरो के अनुसार, यह कार्ड उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जो अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं अवसर पैदा करता है।

जब टैरो रीडिंग में 'द मैजिशियन' कार्ड आता है, तो यह नए अवसरों और नई शुरुआत का संकेत देता है। यह करियर में उन्नति, नए व्यवसाय की शुरुआत, किसी रचनात्मक परियोजना या जीवन के किसी नए चरण में प्रवेश का सूचक हो सकता है। यह कार्ड बताता है कि अब समय है अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने का। व्यक्ति को आत्मसंदेह छोड़कर अपने कौशल और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए।

इस कार्ड का एक महत्वपूर्ण संदेश आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा है। 'द मैजिशियन' यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है। वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। यही आत्मविश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति देता है। टैरो दर्शन में माना जाता है कि जब यह कार्ड आता है, तो व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में संरेखित होने लगते हैं। यही एकरूपता सफलता की कुंजी बनती है।

भाग्य और सफलता के संदर्भ में 'द मैजिशियन' कार्ड को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा व्यक्ति के प्रयासों का समर्थन कर रही है। लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। 'द मैजिशियन' भाग्य और कर्म के संतुलन का प्रतीक है। यानी अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें पहचानकर सही समय पर कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है।

यह कार्ड यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा जादू बाहरी नहीं, बल्कि भीतर होता है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी इच्छाशक्ति ही वह जादू है, जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं हैं, जबकि वास्तव में उनके भीतर छिपी क्षमताएँ ही सबसे बड़ा साधन होती हैं। 'द मैजिशियन' कार्ड इसी छिपी हुई शक्ति को उजागर करता है।

नकारात्मक स्थिति में यह कार्ड चेतावनी भी दे सकता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और कौशल का गलत उपयोग न करे। हेरफेर, छल या दिखावे से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। इसलिए यह कार्ड यह भी याद दिलाता है कि सच्ची सफलता वही है, जो सही इरादों और सही कर्म से प्राप्त हो।

अंततः, टैरो का 'द मैजिशियन' कार्ड यह संदेश देता है कि जीवन की बागडोर आपके हाथों में है। यह समय है अपने भीतर के जादूगर को पहचानने का। यदि आप स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत इच्छाशक्ति और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता और सौभाग्य आपका साथ अवश्य देंगे। यह कार्ड केवल भविष्य की झलक नहीं दिखाता, बल्कि यह विश्वास दिलाता है कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब 'द मैजिशियन' निकलता है, तो समझिए कि जीवन आपको संकेत दे रहा है—अब संदेह छोड़िए, अपनी शक्ति को स्वीकार कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता की राह आपके लिए खुल चुकी है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

देश की नवीकरणीय ऊर्जा में 16.50 प्रतिशत योगदान के साथ गुजरात देश में अग्रसर

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है और परंपरागत ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इस व्यापक आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत की 50 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में नए मानदंड स्थापित किए हैं, जो इस राष्ट्रीय लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। दिसंबर-2025 तक के आँकड़े दर्शाते हैं कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में गुजरात का योगदान सर्वाधिक है। राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुँची है, जो भारत की कुल क्षमता में 16.50 प्रतिशत का योगदान दर्शाती है। इसके अतिरिक्त; गुजरात कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (42.583 गीगावाट) में प्रथम स्थान पर है तथा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (14,820.94 मेगावाट) में भी प्रथम स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता (25,529.40 मेगावाट) में दूसरे स्थान पर है। सोलर रूफटॉप इन्स्टॉलेशन में गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें 11 लाख सोलर रूफटॉप सिस्टम्स के माध्यम से 6,412.80 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है।

सौर ऊर्जा में गुजरात अग्रसर

दिसंबर-2025 तक 25,529.40 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात अग्रसर रहा है। इसमें ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स से 17,771.21 मेगावाट, सोलर रूफटॉप सिस्टम्स से 6,412.80 मेगावाट (जिसमें सूर्य गुजरात द्वारा 2,073.65 मेगावाट, पीएम सूर्य घर योजना द्वारा 1,913 मेगावाट तथा अन्य 2,267.04 मेगावाट), हाइब्रिड परियोजनाओं से 1,172.38 मेगावाट तथा ऑफ-ग्रिड सिस्टम्स (पीएम कुसुम सहित) से 173.01 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। गुजरात में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए चारणका (749 मेगावाट), राधानेसडा (700 मेगावाट) और धोलेरा (300 मेगावाट) में सोलर पार्क कार्यरत हैं। 37.35 गीगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ कच्छ के खावडा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित हो रहा है, जिसमें हाल में 11.33 गीगावाट उत्पादन प्राप्त करने में सफलता मिली है। गुजरात ने 11 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम्स स्थापित करने की उपलब्धि भी हासिल की है; जो आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 6,412.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। गुजरात ने वर्ष 2016 से घरों में छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है और पीएम सूर्य घर योजना के लॉन्च होने तक उसे समर्थन मिला है। इसके कारण भारत के कुल रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशन में राज्य का योगदान 25 प्रतिशत से अधिक हुआ है। कृषि क्षेत्र में पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत 12,700 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सोलर वॉटर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा 89.54 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है।

14,820.94 मेगावाट उत्पादन के साथ पवन ऊर्जा में गुजरात अग्रसर

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात ने प्रथम पवन ऊर्जा नीति लागू करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिसंबर-2025 तक पवन ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की स्थापित क्षमता 14,820.64 मेगावाट है, जिसमें कच्छ का योगदान सर्वाधिक 7,476.73 मेगावाट है। जामनगर (1,867.65 मेगावाट), देवभूमि द्वारका (1,281.26 मेगावाट), अमरेली (973.85 मेगावाट), राजकोट (874.90 मेगावाट), भावनगर (618.80 मेगावाट), मोरबी (568.6 मेगावाट), सुरेन्द्रनगर (456.6 मेगावाट) तथा पाटण (208.2 मेगावाट) जिलों में भी पवन ऊर्जा की उल्लेखनीय स्थापित क्षमता है। राज्य ने 2018 में हाइब्रिड पॉलिसी तथा रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पॉलिसी 2023 अंतर्गत पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं द्वारा 2,398.77 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है। 80 प्रतिशत से अधिक टर्बाइन सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कार्यरत हैं, जहाँ सुदृढ़ ढाँचागत सुविधाएँ तथा अनुकूल प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कारण अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन एवं ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा सेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित तथा पारदर्शी प्रणाली विकसित की है। नेट मीटरिंग नियमों के तहत राज्य ने 6.40 जीडब्लूपी से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की है, जो इसे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाती है।

▸▸ राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट, जिसमें 14,820.94 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 25,529.40 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल

▸▸ रूफटॉप सोलर में गुजरात शीर्ष पर, 11 लाख से अधिक इन्स्टॉलेशन द्वारा 6,412.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन

▸▸ गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास से अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नौकरियों का सृजन

भविष्य के लिए गुजरात सज्ज : 2030 तक 105 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य

गुजरात अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है और हाल में 5,203 परियोजनाएँ चल रही हैं। इन परियोजनाओं में 4,992 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ (32.22 गीगावाट), 72 पवन ऊर्जा परियोजनाएँ (15 गीगावाट) तथा 139 हाइब्रिड एनर्जी परियोजनाएँ (21.15 गीगावाट) शामिल हैं। इनसे 68.37 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त होगी। गांधीनगर में आयोजित आरई इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम में राज्य ने वर्ष 2030 तक 105 गीगावाट उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो भारत के 500 गीगावाट अजीवाश्म ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में 20 प्रतिशत योगदान देगा।

गुजरात की मजबूत नीतियों से ऊर्जा क्षेत्र का विकास

1993 में प्रथम पवन ऊर्जा नीति लागू करने के बाद गुजरात सरकार ने समय-समय पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू की हैं; जिनमें सौर ऊर्जा नीतियाँ (2009, 2015, 2021), वेस्ट टू एनर्जी एंड स्मॉल हाइडल पॉलिसी (2016) और विंड-सोलर हाइब्रिड पॉलिसी (2018) शामिल हैं। 2022 में अपडेटेड वेस्ट टू एनर्जी नीति तथा गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 द्वारा सोलर, विंड, हाइब्रिड तथा वितरण आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए एकीकृत ढाँचा मुहैया कराया गया है। इस नीति के अंतर्गत क्षमता सीमा समाप्त की गई है तथा टैरिफ, ग्रिड चार्ज, ऊर्जा लेखा, क्रॉस सब्सिडी एवं बैंकिंग चार्ज के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त; गुजरात डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी बाइलेटरल प्रोक्योरमेंट (डीआरईबीपी) योजना क्लीन एनर्जी में अग्रणी राज्य के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत बनाती है। तो 2025 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी विशाल क्षमता तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को तेज गति देने पर केन्द्रित है। इसमें ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी, फ्लेक्सिबल कमीशनिंग समयसीमा, पुराने विंड प्रोजेक्ट्स की रीपावरिंग तथा सोलर, पवन एवं हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ बैटरी स्टोरेज का आसान समन्वय सुनिश्चित किया गया है। यह नीति उभरती नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजीस, निजी क्षेत्र की भागीदारी, आरई मैन्युफैक्चरिंग व रिसाइक्लिंग तथा अक्षय-ऊर्जा-सेतु पोर्टल द्वारा डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से नवीनता को प्रोत्साहन देती है।

रेलवे के "मेरी टिकट, मेरी शान" अभियान में भाग लेकर स्नेहा फाउन्डेशन ने जागरूकता फैलाने में किया सहयोग

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने एवं डिजिटल रेलवे सेवाओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे "मेरी टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस, जूनागढ़ एवं वेरावल रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल माध्यमों के जरिए जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अभियान के दौरान स्टेशनों पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आकर्षक क्रिएटिव्स प्रदर्शित किए गए, जिनके माध्यम से यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के रेलवे कर्मचारियों (टिकट निरीक्षकों) ने

यात्रियों से सक्रिय संवाद स्थापित किया तथा उन्हें रेलवन (RailOne) ऐप की विस्तृत जानकारी दी। यात्रियों को ऐप के प्रमुख लाभों जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी एवं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह पहल यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करती है। इसी क्रम में भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग द्वारा "मेरी टिकट – मेरी शान, विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नेहा फाउंडेशन के आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर एवं समाज के हाशिए पर खड़े वंचित बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जागरूकता नारे लगाकर यात्रियों से टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की। इस अभियान के माध्यम से जहां यात्रियों में रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता फैली, वहीं स्नेहा फाउंडेशन के बच्चों को भी रेलवे नियमों, नागरिक जिम्मेदारियों एवं ईमानदार यात्रा के महत्व की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

यह कार्यक्रम बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव सिद्ध हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का भी विकास हुआ। बच्चों को इस जन-जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान कर समाज के प्रति उनकी सकारात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

माननीय केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना द्वारा इंदौर स्टेशन का निरीक्षण एवं रीडेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा

रतलाम। माननीय केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने 31 जनवरी 2026 को इंदौर प्रवास के दौरान इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा रतलाम मंडल द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों एवं यात्री सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने हेतु निर्देशित किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंस्ट्रक्शन कार्यालय में आयोजित बैठक में इंदौर स्टेशन रीडेवलपमेंट सहित क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रेलवे विकास एवं निर्माण कार्यों पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में स्टेशन रीडेवलपमेंट की प्रगति, यात्री सुविधाओं के विस्तार, संरचनात्मक कार्यों, समयबद्ध निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

"इस अवसर पर माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर लालवानी द्वारा माननीय मंत्री

जी को इंदौर क्षेत्र में रेलवे के अंतर्गत संचालित प्रमुख विकास एवं निर्माण परियोजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया। इसमें इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन, इंदौर–खंडवा रेल खंड का आमान परिवर्तन, इंदौर-मनमाड नई रेल लाइन, इंदौर - बुधनी नई रेल लाइन सहित अन्य प्रगतिरत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ लगभग 75 वर्ष पुराने शास्त्री ब्रिज के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं पर भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।"

माननीय श्री सोमन्ना ने इंदौर स्टेशन रीडेवलपमेंट एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक(इंफ्रा) श्री अक्षय कुमार एवं मुख्य इंजीनियर(निर्माण), सहित रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

वर्ष 2026 के पहले ही महीने में राज्य को 4870 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की भेंट मिली

▸▸ जिन कार्यों का शिलान्यास होता है, उनका लोकार्पण उसी सरकार के कार्यकाल में हो; ऐसी समयबद्ध योजना की कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित की है, जिसे गुजरात ने साकार किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री ने सूरतवासियों को 342 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी

▸▸ सूरत महानगर पालिका के 173.78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास

▸▸ सूरत विकास, स्वच्छता और शहरीकरण का मॉडल शहर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ तापी शुद्धिकरण परियोजना के परिणामस्वरूप उकाई से लेकर सूरत तक 85 किमी दूर से आने वाला औद्योगिक गंदा पानी अब तापी नदी में मिलने से रुक गया है : केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

▸▸ गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों का जन भागीदारी से पुनर्विकास पूर्ण, मुख्यमंत्री के करकमलों से लोकार्पण और लाभार्थियों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित हुआ

▸▸ 70 करोड़ रुपए की लागत से डभोली में नव निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम का लोकार्पण

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के लोगों की 'ईज ऑफ लिविंग' बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 के पहले ही महीने में पूरे राज्य में 4870 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्य सरकार ने भेंट दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूरत महानगर पालिका के 173.78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर सूरतवासियों को कुल 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार द्वारा जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाता है, उन कार्यों का लोकार्पण भी उसी सरकार के कार्यकाल में सुनिश्चित हो; ऐसी समयबद्ध योजना और कार्य संस्कृति विकसित की है। उसी कार्य संस्कृति को हमने गुजरात में साकार किया है। राज्य सरकार की 'सार्वजनिक आवास पुनर्विकास योजना-2016' अंतर्गत कतारगाम क्षेत्र के गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की विशेष उपस्थिति में इन आवासों का लोकार्पण किया तथा लाभार्थियों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ भी आयोजित किया।

मुख्यमंत्री ने सूरत के अक्षरवाडी, डभोली और कतारगाम स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में कहा कि सूरत आज देशभर में विकास, स्वच्छता और शहरीकरण का उत्कृष्ट मॉडल बन चुका है। सूरत की स्वच्छता सूरतवासियों में आए सकारात्मक बदलाव और स्वच्छता प्रेम का परिणाम है। अपनी स्वच्छता, अनुशासन और आधुनिक शहरी योजना के बल पर सूरत आज मुंबई जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने सूरत को राज्य के विकास का 'ग्रोथ इंजन' बने हुए सूरत के विकास को उदाहरणीय बताते हुए कहा कि सूरत देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर है। औद्योगिक विकास के कारण समूचे भारत से लोग यहां रोजगार के लिए आकर बस रहे हैं, इसी कारण सूरत को 'मिनी भारत' की उपाधि मिली है। डायमंड और टेक्सटाइल कैपिटल के रूप में पहचाना जाने वाला सूरत आज स्वच्छता, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विजन साकार हो रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण और हमारा संकल्प हम सभी के सहयोग से ही पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि सूरत जैसे शहर देश की आर्थिक गतिशीलता के केंद्र हैं और 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' की यात्रा में नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सूरत को मिले 342 करोड़ रुपए के विकास कार्य शहरी नागरिकों की 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाएंगे। गोटालावाडी टेनामेंट के 1304 आवासों के पुनर्विकास से लाभार्थी परिवारों को सुरक्षित, आधुनिक और आरामदायक आवास मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ई मोबिलिटी, प्रदूषण मुक्त परिवहन और सार्वजनिक आवास योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई शहरी विकास यात्रा के परिणामस्वरूप आज गुजरात सर्वांगीण विकास का मॉडल स्टेट बना है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास हो; इसके लिए सरकार और स्थानीय तंत्र लगातार प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि कतारगाम, वराछा और मोटा वराछा क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक लाइब्रेरी 70 करोड़ रुपए की लागत से कतारगाम में तैयार की जा रही है, जिसका लोकार्पण आगामी तीन महीनों में होगा। यह लाइब्रेरी हजारों युवाओं का उज्ज्वल भविष्य गढ़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि डभोली क्षेत्र में निर्मित नया ऑडिटोरियम कतारगाम, वराछा और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं, कला-प्रेमियों और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

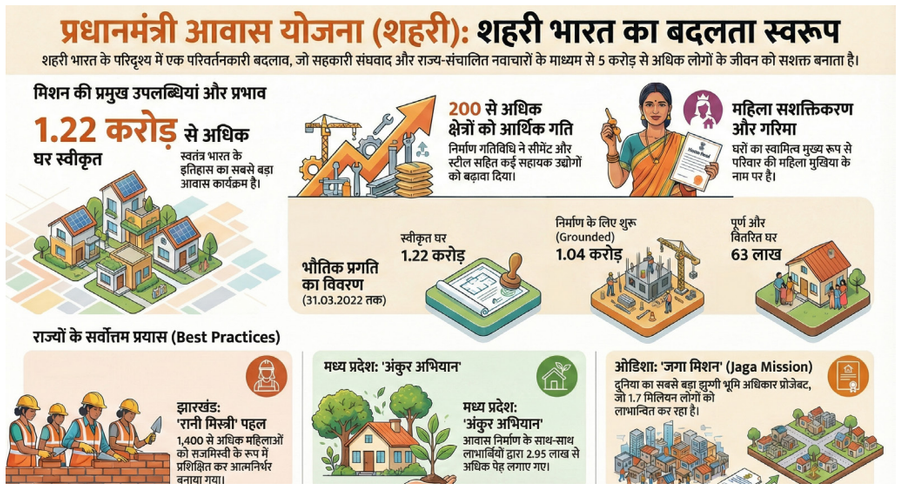

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ डायमंड और टेक्सटाइल कैपिटल के रूप में पहचाना जाने वाला सूरत, स्वच्छता, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अग्रसर

▸▸ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई शहरी विकास यात्रा के परिणामस्वरूप आज गुजरात सर्वांगीण विकास का मॉडल स्टेट बना है

.....

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ शहर के हर क्षेत्र का समान विकास हो; इसके लिए सरकार और स्थानीय तंत्र का निरंतर प्रयास होता है

▸▸ नई परियोजना और विकास परियोजनाएं केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बनती हैं; इन संपत्तियों की देखभाल करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है

नानपुरा गांधी स्मृति, सरदार स्मृति-वराछा और संजीव कुमार ऑडिटोरियम-पाल के बाद अब कतारगाम में भी आधुनिक ऑडिटोरियम बनने से सूरत शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत महानगर पालिका सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत कर रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक उदाहरणात्मक कदम है। श्री संघवी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्मित ऑडिटोरियम, ब्रिज, लाइब्रेरी और स्कूल जैसे परियोजना केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हैं। इनकी सुरक्षा, देखभाल और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि गोटालावाडी टेनामेंट के पुनर्विकास से 1304 परिवारों के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और शुभकामनाएं दी कि परिवार जब अद्भुत खुशी के साथ अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, तो उनके सपने साकार होंगे।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जिस गति से सूरत का विकास हो रहा है, वह अन्य शहरों के लिए उदाहरण है। एक समय अस्वच्छ रहा सूरत आज देश का नंबर-वन स्वच्छ शहर बन चुका है। अगले 50 वर्षों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर पानी की व्यवस्था का समुचित नियोजन किया गया है। देश में 123 से अधिक ब्रिज के साथ सूरत महानगर पालिका नंबर वन बनी है। सरकार और पालिका के अधिकारियों-पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत महानगर पालिका प्रतिवर्ष गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर 400 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर रही है, जो भविष्य में बढ़कर 700 करोड़ रुपए हो जाएगी। वेस्ट वॉटर से इतनी बड़ी आय प्राप्त करने वाली सूरत देश की पहली महानगर पालिका है।

श्री पाटिल ने आगे कहा कि तापी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 931 करोड़ रुपए की तापी शुद्धिकरण परियोजना के चलते उकाई से लेकर सूरत तक 85 किमी दूर से आने वाला औद्योगिक गंदा पानी अब तापी नदी में मिलना बंद हो गया है।

उल्लेखनीय है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से डभोली में नव निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, 12.66 करोड़ रुपए की लागत से जियाव बुडिया लेक गार्डन का लोकार्पण तथा सूरत मनपा द्वारा बनासकांठा जिले के डीसा तहसील के विठोदर गांव में स्थापित 55.56 करोड़ रुपए की लागत से 10 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, लेक गार्डन रीडिंग रूम, अर्बन हेल्थ सेंटर, शेल्टर होम सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा डेनेज, हाइड्रोलिक आदि विभागों के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

महापौर श्री दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि सूरत शहर की सांस्कृतिक विरासत को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से लोकार्पित आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ऑडिटोरियम कतरगामवासियों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट के तहत सूरत महानगर पालिका अपनी आवश्यकता की 28.5 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली महानगर पालिका बन गई है, जिससे प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए की बचत होगी। सूरत महानगर पालिका मूल बिजली बिल में 70 करोड़ रुपए की बचत करने वाली महानगर पालिका बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सूरत वर्ष 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने वाली देश की नंबर वन महानगर पालिका बनेगी। साथ ही, गोटालावाडी में 1304 टेनामेंट के साथ किए गए रिडेवलपमेंट कार्य से निवासियों का अपने पक्के घर का सपना साकार हुआ है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायकगण सर्वश्री पूर्णेशभाई मोदी, विनोदभाई मोरडिया, प्रवीणभाई घोघरी, मनुभाई पटेल, किशोर कानाणी (कुमार), श्रीमती संगीता बेन पाटील, अरविंद राणा, मुकेशभाई पटेल, कांतिभाई बलर, संदीप देसाई, उप महापौर डॉ. नरेंद्र पाटील, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजन पटेल, महानगर पालिका आयुक्त एन. नागराजन, शहर संगठन प्रमुख परेश पटेल सहित कॉर्पोरेटर, महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी-अधिकारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेल्वे

पेंटिंग और मरम्मत के काम

डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA), पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008, ई-टेंडर नोटिस नंबर: BCT/25-26/307 दिनांक 29/01/2026 आमंत्रित करते हैं। काम और स्थान: (1) लोअर परेल: सर्विस बिल्डिंग और अगस्त क्रांति कॉलोनी की समय-समय पर पेंटिंग और छोटी-मोटी मरम्मत (2) सर्विस बिल्डिंग और अगस्त क्रांति की समय-समय पर पेंटिंग और छोटी-मोटी मरम्मत। काम की अनुमानित लागत: ₹ 2,25,15,614.66. EMD: ₹ 2,62,600/-. जमा करने की तारीख और समय: ता.24.02.2026 को 15:00 बजे तक। खोलने की तारीख और समय: ता. 24.02.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं 1070

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिमी रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस ⇌ भुज के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा के दिन	से विस्तृत
09037	बांद्रा टर्मिनस – भुज	द्वि - साप्ताहिक गुरुवार और शनिवार	26.02.2026
09038	भुज - बांद्रा टर्मिनस	द्वि - साप्ताहिक शुक्रवार और रविवार	27.02.2026

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09037 और 09038 की बढ़ी हुई यात्राओं के लिए बुकिंग 01.02.2026 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेंगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें और फॉलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें।

पक्षी-पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में गुजरात की एक और उपलब्धि : कच्छ के गौरव में लगे चार

बन्नी का रतन 'छारी-ढंढ' 'रामसर साइट' घोषित : गुजरात का पांचवां और कच्छ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वेटलैंड बना छारी-ढंढ

(जीएनएस)। गांधीनगर : बन्नी के रतन 'छारी-ढंढ' पक्षी अभयारण्य को आधिकारिक रूप से 'रामसर साइट' घोषित किया गया है, इससे कच्छ के गौरव को चार चांद लग गए हैं। छारी-ढंढ गुजरात का पांचवां और कच्छ का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला वेटलैंड (आर्द्रभूमि) बन गया है। गुजरात के लिए गर्व की बात है कि कच्छ जिले में स्थित छारी ढंढ पक्षी अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गुजरात में रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर पांच हो गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिलने से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्थानीय विकास और वैश्विक पहचान जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि गुजरात वेटलैंड के संरक्षण और संवर्धन में सदैव अग्रसर रहा है। देश के कुल वेटलैंड क्षेत्रफल में गुजरात का हिस्सा 21 फीसदी है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। गुजरात के वेटलैंड लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.8 फीसदी है।

मंत्री श्री मोढवाडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वेटलैंड संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य में मरीन नेशनल पार्क (समुद्री राष्ट्रीय उद्यान) और अभयारण्य, खिजड़िया अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य, छारी ढंढ, कच्छ का छोटा रण-घुड़खर अभयारण्य और पोरबंदर पक्षी अभयारण्य जैसे अनेक वेटलैंड आधारित संरक्षित क्षेत्र हैं। गांधीनगर स्थित गिर फाउंडेशन गुजरात में वेटलैंड इकोसिस्टम की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक शोध, निगरानी कार्यक्रम और वेटलैंड शोध एवं दस्तावेजीकरण में सक्रिय रूप से शामिल है।

उन्होंने कहा कि कच्छ के इको-टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एशिया का

▸▸ छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिलने से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्थानीय विकास, पर्यटन और वैश्विक पहचान सहित सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा : वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

▸▸ 5 रामसर साइट, 8 राष्ट्रीय वेटलैंड सहित देश के सभी वेटलैंड के कुल क्षेत्रफल में 21 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में सबसे आगे, जो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में गुजरात की पहचान को और मजबूत बनाता है : श्री अर्जुन मोढवाडिया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वेटलैंड संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है : श्री अर्जुन मोढवाडिया

सबसे बड़ा घास का मैदान माने जाने वाले बन्नी क्षेत्र के छोर पर स्थित 'छारी-ढंढ' कंजर्वेशन रिजर्व को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वेटलैंड साइट यानी 'रामसर साइट' घोषित किया गया है। नल सरोवर, थोळ, खिजड़िया और वढवाणा के बाद अब 'छारी-ढंढ' गुजरात का पांचवां और कच्छ का पहला रामसर स्थल बन गया है।

श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना गुजरात के लिए गर्व की बात है। इससे राज्य के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। इस मान्यता से छारी-ढंढ वेटलैंड का दीर्घकालिन संरक्षण सुनिश्चित होगा, प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल मजबूत बनेगा और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, रामसर साइट का दर्जा मिलने से क्षेत्र में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर खुलेंगे। पर्यावरण जागरूकता, शैक्षणिक गतिविधियों और समुदाय की सहभागिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली ने कहा कि गुजरात में नल सरोवर, थोळ, खिजड़िया और वढवाणा पक्षी अभयारण्य को पहले ही रामसर साइट की मान्यता मिल चुकी है। अब, छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य के इस सूची में शामिल होने से राज्य की पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड संवर्धन की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो भारत में राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल 115 वेटलैंड में से 8 वेटलैंड गुजरात में हैं। राज्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी गुजरातियों को बधाई देते हुए कहा कि इसके अलावा, राज्य में 19 ऐसे वेटलैंड हैं, जो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल मुहैया कराते हैं।

उल्लेखनीय है कि आज केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 2 फरवरी, 2026 को 'विश्व वेटलैंड दिवस' से पहले उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी-ढंढ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से भारत के रामसर नेटवर्क में दो नए वेटलैंड को शामिल करने की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रामसर नेटवर्क 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्तमान में 98 स्थल हो गया है, जो 276 फीसदी से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नाम की सार्थकता और भौगोलिक महत्व

कच्छी भाषा में 'छारी' का अर्थ क्षार वाली और 'ढंढ' यानी उथला सरोवर। लगभग 227 वर्ग किलोमीटर (22,700 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला यह वेटलैंड रण और घास के मैदान के बीच एक अद्भुत पर्यावास (प्राकृतिक आवास) है। इसे वर्ष 2008 में गुजरात का पहला 'कंजर्वेशन रिजर्व' घोषित किया गया था।

पक्षियों और वन्यजीवों का स्वर्ग

छारी-ढंढ में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। सर्दियों के दौरान यहां साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप के 25,000 से 40,000 तक कॉमन क्रेन (कुंज), वेनेलस ग्रेगेरियस (संघी टिटहरी) और डालमेटियन पेलिकन स्थानांतरण करके आते हैं। इसके अतिरिक्त, लेसर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो और सारस भी यहां दिखाई देते हैं।

इतना ही नहीं, यहां लुप्तप्राय डालमेशियन पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर, ब्लेक-नेक्ड स्टॉर्क और अनेक शिकारी पक्षी भी दिखाई देते हैं। केवल पक्षी ही नहीं, बल्कि यह क्षेत्र चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी (डेजर्ट फॉक्स), स्याहगोश (केरेकल), रेगिस्तानी लोमड़ी और भेड़िये जैसे अनेक वन्यजीवों का भी महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है।

प्रशासन की उपलब्धि

इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता को प्राप्त करने में गुजरात के चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन डॉ. जयपाल सिंह, गांधीनगर वन्य प्राणी विंग की टीम, मुख्य वन संरक्षक (कच्छ फॉरेस्ट सर्कल, भुज) तथा उप वन संरक्षक कच्छ (पश्चिम) वन विभाग भुज के लगातार प्रयास और कार्य निर्णायक रहे हैं। यह उपलब्धि राज्य एवं केंद्र सरकार (वेटलैंड डिवीजन) के निरंतर मार्गदर्शन में वेटलैंड संरक्षण और इसकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप हासिल हुई है।

पर्यटन एवं संरक्षण सकारात्मक प्रभाव

रामसर साइट का दर्जा मिलने से छारी-ढंढ को अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, जिससे कच्छ में इको-टूरिज्म का विकास होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही, इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार फंड और तकनीकी सहायता मिलने का रास्ता भी साफ होगा। वन विभाग कच्छ की इस अमूल्य विरासत को संरक्षित रखने एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

15 अप्रैल तक साबरमती रेलवे स्टेशन पर नए प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के साबरमती स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है जबकि अन्य पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है।

यात्रियों की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 2026 तक आगमन एवं प्रस्थान हेतु नए प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिक-अप एवं ड्रॉप की व्यवस्था की गई है। विवरण इस प्रकार है:

1. प्रस्थान करने वाले यात्रियों हेतु प्रवेश एवं निकास व्यवस्था

▸▸ प्रवेश द्वार (Entry Gate): यात्रियों के वाहनों का प्रवेश MMTS बिल्डिंग (बुलेट ट्रेन स्टेशन) के पास से किया जा रहा है। (डायग्राम में दी गई ग्रीन लाइन के अनुसार)

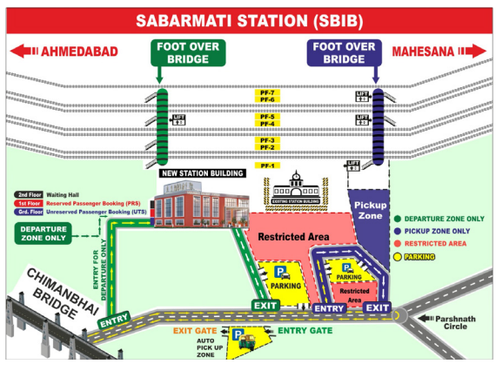

▸▸ यात्री नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में प्रवेश कर लिफ्ट, एस्कलेटर एवं सीढ़ियों के माध्यम से सेकंड फ्लोर से होते हुए सभी प्लेटफार्मों पर जा सकते है।

▸▸ यात्रियों को ड्रॉप करने वाले वाहन पुराने प्रवेश द्वार से बाहर निकल सकते है।

2. आगमन करने वाले यात्रियों हेतु निकास एवं पिक-अप व्यवस्था

▸▸ निकास द्वार (Exit Gate): महेसाणा साइड फुट ओवर ब्रिज के पास से निकास की व्यवस्था की गई है। (डायग्राम में दी गई पर्पल लाइन के अनुसार)

▸▸ इसी स्थान पर यात्रियों के लिए पिक-अप जोन भी बनाया गया है।

3. पार्किंग सुविधा

▸▸ यात्रियों की सुविधा के लिए निकास द्वार के निकट दो स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

4. प्लेटफार्म कनेक्टिविटी

▸▸ सभी प्लेटफार्म (PF-1 से PF-7) दोनों फुट ओवर ब्रिज से कनेक्टेड हैं। (वर्तमान में PF-2 और PF-3 से ट्रेन संचालन पुनर्निर्माण कार्य के कारण बंद है)

5. नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में यात्री सुविधाएं

▸▸ भूतल (Ground Floor): अनारक्षित टिकट बुकिंग (UTS)

▸▸ प्रथम तल (First Floor): आरक्षित टिकट बुकिंग (PRS)

▸▸ द्वितीय तल (Second Floor): प्रतीक्षालय

सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे नई यातायात व्यवस्था, संकेतकों तथा रेलवे एवं आरपीएफ एवं रेलकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

भावनगर-ओखा एक्सप्रेस और भावनगर-साबरमती इंटरसिटी ट्रेन में अतिरिक्त कोच की सुविधा

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेल प्रशासन ने भावनगर-ओखा-भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन (19209/19210) में अस्थायी तौर पर एक थर्ड एसी कोच तथा भावनगर-साबरमती-भावनगर इंटरसिटी ट्रेन (20966/20965) में अस्थाई रूप से 4 अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार अतिरिक्त कोच का विवरण निम्नानुसार है:-

1.ट्रेन नंबर 19209/19210 भावनगर-ओखा-भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच 01.02.2026 से 05.02.2026 तक लगाया जाएगा।

2.ट्रेन नंबर 20966/20965 भावनगर-साबरमती-भावनगर इंटरसिटी में 04 जनरल कोच 01.02.2026 से 05.02.2026 तक लगाया जाएगा।

इस ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ग्रीनफील्ड में भारत का शक्ति प्रदर्शन न्यूजीलैंड पर 46 रन की जीत के साथ टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला में भारतीय टीम ने दमदार संदेश दे दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर न सिर्फ मैच जीता, बल्कि पांच मैचों की सीरीज भी 4-1 से अपने नाम कर ली। यह जीत भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी, संतुलित गेंदबाजी और मजबूत टीम संयोजन का बेहतरीन उदाहरण रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया। हालांकि शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही। संजू सैमसन केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अभिषेक शर्मा ने 30 रनों की तेज पारी खेलने के बाद अपना विकेट गंवा दिया। महज 42 रन पर दो विकेट गिरने से ऐसा लगा कि भारतीय पारी थोड़ी लड़खड़ा सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी।

ईशान किशन ने मैदान पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं किया और सिर्फ 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 शानदार छक्के और 6 चौके शामिल रहे। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 63 रन ठोके। दोनों के बीच हुई 137 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। महज 57 गेंदों में यह साझेदारी पूरी हुई और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भारतीय बल्लेबाजी के इस तूफान के गवाह बने।

पारी के अंतिम ओवरों में हार्दिक पंड्या ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने 17 गेंदों में 42 रन बनाकर स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। भारत ने अंतिम 10 ओवरों में 169 रन जोड़ते हुए 5 विकेट पर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माना जाता है।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी हार मानने के मूड में शुरुआत नहीं की। फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और 38 गेंदों में 80 रन बनाए। रचिन रवींद्र ने भी उनका अच्छा साथ निभाते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 30 रन जड़ दिए। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई और एक समय ऐसा लगा कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और स्विंग से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने पांच विकेट झटककर कीवी बल्लेबाजों को एक के बाद एक पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल ने भी शानदार सहयोग देते हुए तीन अहम विकेट अपने नाम किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट लिया। लगातार गिरते विकेटों के दबाव में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवर में 225 रन पर ऑलआउट हो गई।

इस तरह भारत ने 46 रनों से मुकाबला जीत लिया और सीरीज का अंत शानदार अंदाज में किया। भारत पहले ही शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुका था। चौथे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वापसी जरूर की थी, लेकिन निर्णायक मैच में भारतीय टीम ने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाई।

बिना अदालती आदेश जेल से बाहर आया गैंगस्टर, बांदा कारागार में मचा प्रशासनिक भूचाल

(जीएनएस)। बांदा। उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन, पुलिस और न्यायिक तंत्र तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जिला कारागार बांदा से कुख्यात गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना की कथित तौर पर बिना किसी स्पष्ट न्यायिक आदेश के रिहाई ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आते ही कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हरकत में आ गया और प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही मानते हुए बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है।

रविंद्र उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर-63 में दर्ज एक आपराधिक मामले में वांछित था। वह पहले से ही एक अन्य मुकदमे में बांदा जिला कारागार में निरुद्ध था। इसी बीच नोएडा पुलिस ने 28 जनवरी को उसके खिलाफ बी-वारंट जारी कराया, जिसके तहत 29 जनवरी को उसे अदालत में पेश किया गया। आमतौर पर बी-वारंट पर पेश किए गए किसी आरोपी को बिना स्पष्ट रिहाई आदेश के जेल से बाहर नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इस मामले में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार 29 जनवरी को पेशी के बाद शाम 6 बजकर 39 मिनट पर आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि संबंधित मुकदमे में न्यायिक कार्यवाही अभी जारी थी और किसी भी दस्तावेज में उसकी रिहाई का स्पष्ट आदेश दर्ज नहीं था। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और किस स्तर पर लापरवाही बरती गई।

गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर मानते हुए जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से

पूछा है कि बी-वारंट पर तलब आरोपी को किन परिस्थितियों में रिहा किया गया और यदि यह रिहाई अवैध थी, तो इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों न कराई जाए। अदालत की टिप्पणी ने इस प्रकरण को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रशासनिक गलती, बल्कि संभावित आपराधिक लापरवाही की आशंका भी जताई गई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेल प्रशासन को यह भली-भांति जानकारी थी कि आरोपी को नोएडा के मामले में बी-वारंट पर अदालत में पेश किया गया है। इसके बावजूद यदि उसे रिहा कर दिया गया, तो यह सामान्य भूल नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। अदालत का यह रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कानूनी शिकंजा और कस सकता है। वहीं, जेल प्रशासन ने अपने बचाव में अलग तर्क पेश किया है। जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम का कहना है कि रवि काना के खिलाफ दर्ज 20 से अधिक मामलों में पहले ही रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके थे। उनके अनुसार अंतिम रिहाई आदेश 28 जनवरी की सुबह जारी हुआ था। 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई, लेकिन शाम तक कोई नया कस्टडी वारंट या लिखित निर्देश जेल को प्राप्त नहीं हुआ। जेल अधीक्षक का दावा है कि वैध निरुद्ध आदेश के अभाव में नियमों के तहत आरोपी को रिहा किया गया। उनका यह भी कहना है कि संबंधित कस्टडी वारंट बाद में रात करीब 7 बजकर 45 मिनट पर जेल की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर प्राप्त हुआ, जब आरोपी को छोड़ा जा चुका था। हालांकि, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आरोपी को बी-वारंट पर पेश किया गया था, तो उसकी रिहाई से पहले संबंधित अदालत या पुलिस से स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं पूछी गई। इसी बिंदु को लेकर जेलर विक्रम सिंह यादव की भूमिका संदेह के घेरे में आई और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। एक कुख्यात गैंगस्टर, जिसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं, यदि बिना स्पष्ट आदेश जेल से बाहर आ सकता है, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। अब निगाहें न्यायिक जांच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि यह महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में एफआईआर, विभागीय कार्रवाई और अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 13062 रुपये और चांदी वायदा में 72604 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 592 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 23 से 29 जनवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 4391372.37 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 853290.67 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3537958.21 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 49333 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 50641.76 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 724918.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 158889 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 180779 रुपये और नीचे में 155248 रुपये पर पहुंचकर, 156341 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13062 रुपये या 8.35 फीसदी के ऊछाल के साथ 169403 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 14704 रुपये या 10.96 फीसदी की तेजी के संग 148867 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1926 रुपये या 11.45 फीसदी की मजबूती के साथ 18746 रुपये प्रति 1 ग्राम सप्ताह के अंत में बंद हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 158143 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 182130 रुपये और नीचे में 155631 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 14421 रुपये या 9.21 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 170954 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 162589 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 190018 रुपये और नीचे में 161900 रुपये पर पहुंचकर, 161742 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 22683 रुपये या 14.02 फीसदी की तेजी के संग 184425 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 853290 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3537958 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 724918 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 49333 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 333333 रुपये के भाव पर खूलकर, 420048 रुपये के उच्च और 327502 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 327289 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 72604 रुपये या 22.18 फीसदी के ऊछाल के साथ 399893 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 78311 रुपये या 23.56 फीसदी बढ़कर 410704 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 78583 रुपये या 23.64 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 411059 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 69299.43 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 108.2 रुपये या 8.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1411.5 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 23.9 रुपये या 7.54 फीसदी तेज होकर सप्ताह के अंत में यह कॉन्ट्रैक्ट 340.75 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 23.35 रुपये या 7.34 फीसदी बढ़कर 341.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10.1 रुपये या 5.27 फीसदी की बढ़त के साथ सप्ताह के अंत में 201.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 59025.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5495 रुपये के भाव पर खूलकर, 6135 रुपये के उच्च और 5475 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 592 रुपये या 10.88 फीसदी की मजबूती के साथ 6032 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 589 रुपये या 10.82 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 6031 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 328 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 363.3 रुपये के उच्च और 313.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 326.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 25.6 रुपये या 7.84 फीसदी की मजबूती के साथ 352 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 25.8 रुपये या 7.92 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 351.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 976 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 13.1 रुपये या 1.34 फीसदी की तेजी के संग 992.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 432316.08 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 292601.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 58128.77 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 5211.94 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 661.69 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 5149.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 9549.62 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 49399.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 44.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 4226 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 30090 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19027 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 254253 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 32630 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8798 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18826 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 40699 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18277 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16680 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 43500 पॉइंट पर खूलकर, 52600 के उच्च और 43300 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 6344 पॉइंट बढ़कर 49333 पॉइंट के स्तर पर